

UPPCS PRE 24 MA ANSWER- 4

1. सूची I (मौलिक अधिकार) को सूची II (सम्बंधित अनुच्छेद) से सुमेलित कीजिये:

सूची I	सूची II
A. शोषण के विरुद्ध अधिकार	1. अनुच्छेद 25-28
B. धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार	2. अनुच्छेद 29-30
C. संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार	3. अनुच्छेद 23-24
D. संवैधानिक उपचारों का अधिकार	4. अनुच्छेद 32

नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए:

- (a) A-3, B-1, C-2, D-4
(b) A-4, B-1, C-2, D-3
(c) A-3, B-2, C-1, D-4
(d) A-4, B-2, C-1, D-3

2. भारतीय संविधान के अनुच्छेद '12' के अनुसार 'भाग 3' के प्रयोजन के लिए राज्य की परिभाषा में सम्मिलित है/हैं?

1. लोकसभा
2. राज्य विधान परिषद
3. ग्राम पंचायतें
4. संयुक्त राष्ट्र संघ

कूट:

- (a) केवल 1 और 2
(b) केवल 1, 2 और 3
(c) केवल 1, 3 और 4
(d) 1, 2, 3 और 4

1. उत्तर -(a)

भारत का संविधान छह मौलिक अधिकार प्रदान करता है -

- समता का अधिकार (अनुच्छेद 14-18)
- स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19-22)
- शोषण के विरुद्ध अधिकार (अनुच्छेद 23-24)
- धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 25-28)
- संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार (अनुच्छेद 29-30)
- संवैधानिक उपचारों का अधिकार (अनुच्छेद 32)

मूलतः संविधान में संपत्ति का अधिकार (अनुच्छेद 31) भी शामिल था। हालाँकि इसे 44वें संविधान अधिनियम, 1978 द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था। इसे संविधान के 'भाग XII' में अनुच्छेद 300 (A) के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया है।

अतिरिक्त ज्ञान:

- भारतीय संविधान में नागरिकों के 'मौलिक अधिकारों' का वर्णन संविधान के 'भाग 3' में 'अनुच्छेद 12 से 35 तक' किया गया है।

2. उत्तर -(b)

भाग III: मूल अधिकार

अनुच्छेद 12 - 'भाग 3' के प्रयोजन के लिए राज्य की परिभाषा

इसके अनुसार 'राज्य' में निम्नलिखित शामिल हैं -

- संघ सरकार के विधायी और कार्यकारी अंग
 - भारत सरकार
 - भारतीय संसद - लोकसभा, राज्यसभा
- राज्य सरकार के विधायी और कार्यकारी अंग
 - राज्य सरकारें
 - राज्य विधानमंडल - विधान सभा, राज्यविधान परिषद
- सभी स्थायी प्राधिकारी
 - नगर पालिकाएँ - नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायतें
 - पंचायतें - जिला पंचायतें, मंडल पंचायतें, ग्राम पंचायतें

	<ul style="list-style-type: none"> ○ जिला बोर्ड ○ सुधार ट्रस्ट, आदि। ● वैधानिक और गैर-सांविधिक प्राधिकरण <ul style="list-style-type: none"> ○ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ○ राष्ट्रीय महिला आयोग ○ राष्ट्रीय विधि आयोग ○ राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण ○ राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ○ सशस्त्र बल न्यायाधिकरण ○ केंद्रीय जांच ब्यूरो ○ केंद्रीय सतर्कता आयोग ○ लोकपाल और लोकायुक्त ○ LIC, ONGC, SAIL आदि <p>संजय बहेल बनाम भारत संघ और अन्य मामला</p> <ul style="list-style-type: none"> ● यह मामला संयुक्त राष्ट्र (विशेषाधिकार और प्रतिरक्षा) अधिनियम, 1947 के तहत संयुक्त राष्ट्र संगठनों (UNO) द्वारा प्राप्त प्रतिरक्षा के मुद्दे से संबंधित है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने मई 2019 में घोषित किया कि UNO भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत परिभाषित एक 'राज्य' नहीं है। <div data-bbox="609 850 1550 1270" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>अतिरिक्त ज्ञान:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● अनुच्छेद 12 में 'राज्य' के रूप में न्यायपालिका (उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, या राज्य/जिला न्यायालय) का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है। हालाँकि, न्यायपालिका के अंग ऐसे नियम नहीं बना सकते हैं जो स्वयं मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। ● रूपा अशोक हुर्रा बनाम अशोक हुर्रा मामला - सुप्रीम कोर्ट ने पुष्टि की कि किसी भी न्यायिक कार्यवाही द्वारा मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है और यह भी कि उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 12 के दायरे में नहीं आते हैं। </div>
<p>3. भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 13' के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. यह घोषणा करता है कि "मूल अधिकारों से असंगत या उन्हें कम करने वाली विधियाँ शून्य होंगी"। 2. यह अनुच्छेद न्यायालय को नागरिकों के मूल अधिकारों का प्रहरी बनाता है। <p>उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?</p> <p>(a) केवल 1</p> <p>(b) न तो 1, न ही 2</p> <p>(c) केवल 2</p> <p>(d) 1 और 2 दोनों</p>	<p>3. उत्तर -(d)</p> <p>अनुच्छेद 13</p> <ul style="list-style-type: none"> ● भारतीय संविधान का 'अनुच्छेद 13' यह घोषणा करता है कि "मूल अधिकारों से असंगत या उन्हें कम करने वाली विधियाँ शून्य होंगी"। अर्थात् ये विधियाँ 'न्यायिक समीक्षा' के योग्य हैं। ● यह उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों को शक्ति प्रदान करता है जिनके आधार पर मूल अधिकारों से असंगत विधियों को वे अवैध घोषित करते हैं। ● यह न्यायालय को नागरिकों के मूल अधिकारों का प्रहरी बनाता है। <div data-bbox="609 1680 1550 1974" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>अतिरिक्त ज्ञान:</p> <p>अनुच्छेद 13 में निम्न उपबंध किये गए हैं -</p> <ul style="list-style-type: none"> ● अनुच्छेद -13 (1) - इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले भारत के राज्यक्षेत्र में प्रवृत्त सभी विधियाँ उस सीमा तक शून्य होंगी जिस तक वे इस भाग के उपबंधों से असंगत हैं। ● अनुच्छेद -13 (2) - राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो इस भाग द्वारा </div>

	<p>प्रदत्त अधिकारों को छीनती है या न्यून करती है और इस खंड के उल्लंघन में बनाई गई प्रत्येक विधि उल्लंघन की सीमा तक शून्य होगी।</p> <ul style="list-style-type: none"> • अनुच्छेद -13 (3) - इस अनुच्छेद में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, - <ul style="list-style-type: none"> ○ (क) "विधि" के अंतर्गत भारत के राज्यक्षेत्र में विधि का बल रखने वाला कोई अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनियम, अधिसूचना, रूढ़ि या प्रथा है ; ○ (ख) "प्रवृत्त विधि" के अंतर्गत भारत के राज्यक्षेत्र में किसी विधान-मंडल या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस संविधान के प्रारंभ से पहले पारित या बनाई गई विधि है जो पहले ही निरसित नहीं कर दी गई है, चाहे ऐसी कोई विधि या उसका कोई भाग उस समय पूर्णतया या विशिष्ट क्षेत्रों में प्रवर्तन में नहीं है। • अनुच्छेद -13 (4) - इस अनुच्छेद की कोई बात अनुच्छेद 368 के अधीन किए गए इस संविधान के किसी संशोधन को लागू नहीं होगी।
<p>4. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 14' के तहत राज्य, भारत के राज्यक्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। 2. 'विधि के समान संरक्षण' की अवधारणा ब्रिटिश संविधान से ली गई है। <p>उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?</p> <p>(a) केवल 2 (b) न तो 1, न ही 2 (c) केवल 1 (d) 1 और 2 दोनों</p>	<p>4. उत्तर -(c)</p> <p>विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण (अनुच्छेद 14)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 'अनुच्छेद 14' के तहत राज्य, भारत के राज्यक्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। • यह अधिकार नागरिकों तथा विदेशियों के साथ-साथ कंपनियों जैसे कानूनी व्यक्तियों को भी प्रदान किया गया है। • 'विधि के समक्ष समानता' की अवधारणा ब्रिटिश मूल की है। • 'विधि के समान संरक्षण' की अवधारणा अमेरिकी संविधान से ली गई है। <p>अतिरिक्त ज्ञान:</p> <p>विधि के समक्ष समानता</p> <ul style="list-style-type: none"> • 'विधि के समक्ष समानता' की अवधारणा ब्रिटिश मूल की है, इसका अर्थ है - <ul style="list-style-type: none"> ○ किसी भी व्यक्ति के पक्ष में किसी भी प्रकार के विशेषाधिकार का अभाव, ○ विधि के समक्ष सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार, ○ कोई भी व्यक्ति विधि से बढ़कर नहीं है। <p>'विधियों के समान संरक्षण'</p> <ul style="list-style-type: none"> • 'विधि के समान संरक्षण' की अवधारणा अमेरिकी संविधान से ली गई है। इसका अर्थ है - <ul style="list-style-type: none"> ○ कानूनों द्वारा प्रदत्त विशेषाधिकारों और दायित्वों दोनों में समान परिस्थितियों में समान व्यवहार। ○ विधि के माध्यम से दिये अधिकारों में समान परिस्थिति में समान व्यवहार। ○ सभी व्यक्तियों के साथ बिना किसी भेदभाव के समान व्यवहार किया जाना चाहिए। <p>'उच्चतम न्यायालय' ने निर्णय दिया है कि अनुच्छेद 14 में निहित 'विधि का शासन' संविधान की एक 'मूलभूत विशेषता' है, और इसलिए इसे संविधान संशोधन द्वारा समाप्त</p>

	<div> <p>नहीं किया जा सकता।</p> </div>
<p>5. भारतीय संविधान का 'अनुच्छेद 15' विभेद का प्रतिषेध करता है -</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. धर्म के आधार पर 2. लिंग के आधार पर 3. नागरिकता के आधार पर 4. जन्म स्थान के आधार पर <p>कूट:</p> <p>(a) केवल 1 और 2</p> <p>(b) 1, 2, 3 और 4</p> <p>(c) केवल 1, 2 और 4</p> <p>(d) केवल 1, 2 और 3</p>	<p>5. उत्तर -(c)</p> <p>भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 - धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध</p> <ul style="list-style-type: none"> • इसमें स्पष्ट रूप से इस बात का उल्लेख है कि किसी नागरिक के विरुद्ध धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। • उक्त आधारों पर किसी व्यक्ति को दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश करने तथा पूर्णतः या अंशतः राज्य निधि से पोषित या जनसामान्य के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नान घाटों आदि का प्रयोग करने से मना नहीं किया जा सकता है। • हालांकि राज्य को इस बात की अनुमति है कि वह समाज के वंचित वर्गों एवं महिलाओं के उत्थान हेतु सकारात्मक विभेद कर सकता है। • 'अनुच्छेद 15' केवल भारतीय नागरिकों को संरक्षण देता है विदेशियों को नहीं, अतः इसके अनुसार राज्य 'नागरिकता' के आधार पर विभेद कर सकता है। <div> <p>अतिरिक्त ज्ञान:</p> <p>भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 15' के अपवाद</p> <ul style="list-style-type: none"> • राज्य को महिलाओं और बच्चों के लाभ के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार है, जैसे स्थानीय निकायों में सीटें आरक्षित करना या बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना। • राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों, साथ ही अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उत्थान के लिए विशेष उपाय करने का अधिकार है, जैसे सार्वजनिक शिक्षण संस्थानों में सीट आरक्षण या शुल्क रियायतें। • राज्य को अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को छोड़कर, निजी शिक्षण संस्थानों सहित शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के मामले में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के उत्थान के लिए विशेष उपाय करने का अधिकार है, चाहे राज्य द्वारा सहायता प्राप्त हो या नहीं। • राज्य को समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए विशेष उपाय करने का अधिकार है। इसके अतिरिक्त, राज्य ऐसे वर्गों के लिए शैक्षणिक संस्थानों में (अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को छोड़कर) 10% तक सीटें आरक्षित कर सकता है। </div>
<p>6. भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन-सा अनुच्छेद नियुक्तियों या पदों के आरक्षण से सम्बंधित है?</p> <p>(a) अनुच्छेद 16(1)</p> <p>(b) अनुच्छेद 16(2)</p> <p>(c) अनुच्छेद 16(3)</p> <p>(d) अनुच्छेद 16(4)</p>	<p>6. उत्तर -(d)</p> <p>'अनुच्छेद - 16' (लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता)</p> <ul style="list-style-type: none"> • अनुच्छेद 16(1) - राज्य के अधीन किसी पद नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी। • अनुच्छेद 16(2) - राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के संबंध में केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान, निवास या इनमें से किसी के आधार पर न तो कोई नागरिक अपात्र होगा और न उससे विभेद किया जाएगा।

- **अनुच्छेद 16(3)** - इस अनुच्छेद की कोई बात संसद को कोई ऐसी विधि बनाने से निवारित नहीं करेगी जो किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र की सरकार के या उसमें के किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन वाले किसी वर्ग या वर्गों के पद पर नियोजन या नियुक्ति के संबंध में ऐसे नियोजन या नियुक्ति से पहले उस राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के भीतर निवास विषयक कोई अपेक्षा विहित करती है। (7वां संविधान संशोधन, 01-11-1956)
- **अनुच्छेद 16(4)** - इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में, जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिए उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी।
- **अनुच्छेद 16(4)(क)** - इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में, जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, राज्य के अधीन सेवाओं में किसी वर्ग या वर्गों के पदों पर, पारिणामिक ज्येष्ठता सहित, प्रोन्नति के मामले में आरक्षण के लिए उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। (77वां संविधान संशोधन, और 85वां संविधान संशोधन (2001) , 17-06-1995)
- **अनुच्छेद 16(4)(ख)** - इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को किसी वर्ष में किन्हीं न भरी गई ऐसी रिक्तियों को, जो खंड (4) या खंड (4क) के अधीन किए गए आरक्षण के लिए किसी उपबंध के अनुसार उस वर्ष में भरी जाने के लिए आरक्षित हैं, किसी उत्तरवर्ती वर्ष या वर्षों में भरे जाने के लिए पृथक् वर्ग की रिक्तियों के रूप में विचार करने से निवारित नहीं करेगी और ऐसे वर्ग की रिक्तियों पर उस वर्ष की रिक्तियों के साथ जिसमें वे भरी जा रही हैं, उस वर्ष की रिक्तियों की कुल संख्या के संबंध में पचास प्रतिशत आरक्षण की अधिकतम सीमा का अवधारण करने के लिए विचार नहीं किया जाएगा। (81वां संविधान संशोधन 09-06-2000)
- **अनुच्छेद 16(5)** - इस अनुच्छेद की कोई बात किसी ऐसी विधि के प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी जो यह उपबंध करती है कि किसी धार्मिक या सांप्रदायिक संस्था के कार्यकलाप से संबंधित कोई पदधारी या उसके शासी निकाय का कोई सदस्य किसी विशिष्ट धर्म का मानने वाला या विशिष्ट संप्रदाय का ही हो।
- **अनुच्छेद 16(6)** - इस अनुच्छेद की कोई बात, राज्य को विद्यमान आरक्षण के अतिरिक्त तथा प्रत्येक प्रवर्ग में पदों के अधिकतम दस प्रतिशत के अध्यक्षीन, खंड (4) में उल्लिखित वर्गों से भिन्न नागरिकों के आर्थिक रूप से दुर्बल किन्हीं वर्गों के पक्ष में नियुक्तियों और पदों के आरक्षण के लिए कोई भी उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। (103वां संविधान संशोधन, 14-01-2019)

अतिरिक्त ज्ञान:

आरक्षण व्यवस्था और भारत

- भारत की सदियों पुरानी जाति व्यवस्था और छुआछूत जैसी कुप्रथाएँ देश में आरक्षण व्यवस्था की उत्पत्ति का प्रमुख कारण हैं। सरल शब्दों में आरक्षण का अभिप्राय सरकारी नौकरियों, शैक्षणिक संस्थानों और विधायिकाओं में किसी एक वर्ग विशेष की पहुँच को आसान बनाने से है।
- इन वर्गों को उनकी जातिगत पहचान के कारण ऐतिहासिक रूप से कई अन्यायों का सामना करना पड़ा है।

	<ul style="list-style-type: none"> वर्ष 1882 में विलियम हंटर और ज्योतिराव फुले ने मूल रूप से जाति आधारित आरक्षण प्रणाली की कल्पना की थी। आरक्षण की मौजूदा प्रणाली को सही मायने में वर्ष 1933 में पेश किया गया था जब तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय दिया। विदित है कि इसके तहत मुसलमानों, सिखों, भारतीय ईसाइयों, एंग्लो-इंडियन, यूरोपीय और दलितों के लिये अलग-अलग निर्वाचन क्षेत्रों का प्रावधान किया गया। आज़ादी के पश्चात् शुरुआती दौर में मात्र SC और ST समुदाय से संबंधित लोगों के लिये ही आरक्षण की व्यवस्था की गई थी, किंतु वर्ष 1991 में मंडल आयोग की सिफारिशों के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) को भी आरक्षण की सीमा में शामिल कर लिया गया।
<p>7. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:</p> <ol style="list-style-type: none"> भारतीय संविधान 'अस्पृश्यता' को समाप्त करता है एवं इसके अभ्यास को निषिद्ध करता है। भारतीय संविधान के 'भाग 3' में 'अस्पृश्यता' शब्द को परिभाषित किया गया है। <p>उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?</p> <p>(a) 1 और 2 दोनों (b) केवल 1 (c) न तो 1, न ही 2 (d) केवल 2</p>	<p>7. उत्तर -(b)</p> <p>भारतीय संविधान का 'अनुच्छेद 17' (अस्पृश्यता का अंत)</p> <ul style="list-style-type: none"> यह प्रावधान 'अस्पृश्यता' को समाप्त करता है और किसी भी रूप में इसके अभ्यास को निषिद्ध करता है। इसके अनुसार अस्पृश्यता के आधार पर अक्षमता को लागू करने वाले किसी भी कार्य को दंडनीय अपराध माना जाएगा। हालाँकि, संविधान या 1955 के नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम (इस प्रावधान को लागू करने के लिए अधिनियमित अधिनियम) में 'अस्पृश्यता' शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>अतिरिक्त ज्ञान:</p> <ul style="list-style-type: none"> अस्पृश्यता का तात्पर्य कुछ जातियों में जन्म लेने के कारण कुछ वर्गों के व्यक्तियों पर लगाई गई सामाजिक नियोग्यताओं से है। इसलिए, यह कुछ व्यक्तियों के सामाजिक बहिष्कार या धार्मिक सेवाओं से उनके बहिष्कार आदि को शामिल नहीं करता है। </div>
<p>8. भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 18' के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:</p> <ol style="list-style-type: none"> यह भारतीय नागरिकों को किसी भी विदेशी राज्य से उपाधियाँ स्वीकार करने से रोकता है। इसके अनुसार राज्य के अधीन किसी लाभ के पद या विश्वास के पद पर आसीन कोई विदेशी, राष्ट्रपति की सहमति के बिना किसी विदेशी राज्य से उपाधियाँ स्वीकार नहीं कर सकता। <p>उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?</p> <p>(a) न तो 1, न ही 2 (b) केवल 1</p>	<p>8. उत्तर -(d)</p> <p>भारतीय संविधान का 'अनुच्छेद 18' (उपाधियों का उन्मूलन)</p> <p>भारतीय संविधान का 'अनुच्छेद 18' उपाधियों और भेदों के उन्मूलन से संबंधित है। इसमें चार प्रावधान हैं -</p> <ul style="list-style-type: none"> यह राज्य को किसी भी व्यक्ति, चाहे वह नागरिक हो या विदेशी, को सैन्य या शैक्षणिक विशिष्टताओं को छोड़कर कोई भी उपाधि देने से रोकता है। यह भारतीय नागरिकों को किसी भी विदेशी राज्य से उपाधियाँ स्वीकार करने से रोकता है। राज्य के अधीन किसी लाभ के पद या विश्वास के पद पर आसीन कोई विदेशी, राष्ट्रपति की सहमति के बिना किसी विदेशी राज्य से उपाधियाँ स्वीकार नहीं कर सकता। राष्ट्रपति की सहमति के बिना न तो नागरिकों और न ही राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का कोई पद रखने वाले विदेशियों को किसी भी विदेशी राज्य से या उसके अधीन कोई उपहार, वेतन या पद स्वीकार करने की अनुमति है।

<p>(c) केवल 2</p> <p>(d) 1 और 2 दोनों</p>	<p>अतिरिक्त ज्ञान:</p> <p>‘अनुच्छेद 18’ के प्रावधानों के संबंध में दो बातों को ध्यान दिया जाना चाहिए -</p> <ul style="list-style-type: none"> इस अनुच्छेद द्वारा औपनिवेशिक राज्यों द्वारा प्रदान किये गए महाराजा, दीवान आदि जैसे वंशानुगत उपाधियों को प्रतिबंधित किया गया है। यह अनुच्छेद राष्ट्रीय पुरस्कारों जैसे भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री को प्रतिबंधित नहीं करता है। हालाँकि, उन्हें पुरस्कार विजेताओं के नाम के साथ प्रत्यय या उपसर्ग के रूप में उपयोग नहीं किया जाना चाहिए।
<p>9. ‘उच्चतम न्यायालय’ ने अनुच्छेद 19(1)(A) के तहत ‘वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता’ में सम्मिलित किया है -</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. प्रेस की स्वतंत्रता 2. शांति का अधिकार 3. सूचना का अधिकार 4. ‘हड़ताल’ का अधिकार <p>कूट:</p> <p>(a) केवल 2 और 3</p> <p>(b) केवल 1, 2 और 3</p> <p>(c) केवल 1, 3 और 4</p> <p>(d) केवल 3 और 4</p>	<p>9. उत्तर -(b)</p> <p>अनुच्छेद 19(1)(A) - ‘उच्चतम न्यायालय’ ने वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में निम्नलिखित को सम्मिलित किया है -</p> <ul style="list-style-type: none"> अपने या किसी अन्य के विचारों को प्रसारित करने का अधिकार। प्रेस की स्वतंत्रता। व्यावसायिक विज्ञापन की स्वतंत्रता। फोन टैपिंग के विरुद्ध अधिकार। प्रसारण करने का अधिकार। किसी राजनीतिक दल या संगठन के द्वारा आयोजित बंद के विरुद्ध अधिकार। सरकारी गतिविधियों की सूचना का अधिकार। शांति का अधिकार। किसी समाचार पत्र पर पूर्व प्रतिबंध के विरुद्ध अधिकार। प्रदर्शन एवं विरोध का अधिकार, परंतु इसमें ‘हड़ताल’ का अधिकार शामिल नहीं है। <p><small>join telegram https://t.me/pcsstudies1</small></p> <p>अतिरिक्त ज्ञान:</p> <p>अनुच्छेद 19 - वाक्-स्वतंत्रता आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण</p> <ul style="list-style-type: none"> मूलतः अनुच्छेद 19 में 7 मूल अधिकार थे, परंतु संपत्ति के क्रय, अधिग्रहण और विक्रय के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 के माध्यम से समाप्त कर दिया गया। अतः वर्तमान में इसमें 6 मूल अधिकार शेष हैं। <p>सभी नागरिकों को -</p> <ul style="list-style-type: none"> (A) वाक्-स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति-स्वातंत्र्य का, (B) शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन का, (C) संगम या संघ बनाने का, (D) भारत के राज्यक्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण का, (E) भारत के राज्यक्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बस जाने का, [और] (G) कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार होगा।
<p>10. निम्नलिखित में से कौन-सा/से ‘राज्य’ द्वारा वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 19(1)(A)) पर प्रतिबंध का/के आधार है/हैं?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. विदेशी राज्यों से मित्रवत संबंध 	<p>10. उत्तर -(a)</p> <p>राज्य द्वारा वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 19(1)(A)) पर प्रतिबंध के आधार-</p> <ul style="list-style-type: none"> भारत की एकता एवं संप्रभुता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों से मित्रवत संबंध, सार्वजनिक आदेश, नैतिकता की स्थापना, न्यायालय की अवमानना, किसी

<p>2. नैतिकता की स्थापना 3. न्यायालय की अवमानना 4. किसी अपराध में संलिप्तता/उकसाना</p> <p>कूट: (a) 1, 2, 3 और 4 (b) केवल 1, 2 और 3 (c) केवल 1, 3 और 4 (d) केवल 2 और 3</p>	<p>अपराध में संलिप्तता/उकसाना आदि।</p> <p><u>अतिरिक्त ज्ञान:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • 'वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता' में प्रेस की स्वतंत्रता भी सम्मिलित है। इससे जुड़ा ऐतिहासिक मामला मेनका गांधी बनाम भारत संघ है। उस मामले में अदालत ने कहा था कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की कोई भौगोलिक सीमा नहीं है और यह किसी भी नागरिक के लिए भारत के साथ-साथ विदेशों में जानकारी एकत्र करने और विचारों का आदान-प्रदान करने का अधिकार रखती है। • भारतीय संविधान का 'अनुच्छेद 19 (1)(G)' भारत के प्रत्येक नागरिक को उसकी इच्छा के अनुसार व्यवसाय आदि करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। यहां व्यवसाय से संदर्भ वैध व्यवसाय से है, न कि अवैध व्यवसाय से। इस मूल अधिकार पर युक्ति युक्त प्रतिबंध आरोपित किए गए हैं, जैसे राज्य का अधिकार है कि वह विशेष प्रकार के व्यवसायों के लिए तकनीकी ज्ञान या प्रशिक्षण की अर्हता निश्चित कर सकता है।
<p>11. भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 358' के अनुसार 'अनुच्छेद 19' स्वतः निलंबित हो जाता है यदि आपातकाल का आधार है -</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. बाह्य आक्रमण 2. वित्तीय अस्थिरता 3. राज्यों में सवैधानिक तंत्र की विफलता <p>कूट: (a) केवल 1 (b) 1, 2 और 3 (c) केवल 1 और 3 (d) केवल 2</p>	<p>11. उत्तर -(a) अनुच्छेद 19 का निलंबन</p> <ul style="list-style-type: none"> • जब 'अनुच्छेद 352' के अधीन आपातकाल की घोषणा की जाती है तो 'अनुच्छेद 358' के अनुसार अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाता है। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 के माध्यम से प्रावधान किया गया कि अनुच्छेद 19 (1) में उल्लिखित स्वतंत्रताओं को सिर्फ तभी निलंबित किया जा सकेगा जब आपातकाल की उद्घोषणा युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण के कारण हुई हो। <p><u>अतिरिक्त ज्ञान:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • '44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978' के माध्यम से 'अनुच्छेद 359' में संशोधन करके यह व्यवस्था की गई कि अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को राष्ट्रपति के आदेश द्वारा भी निलंबित नहीं किया जा सकेगा। इससे पूर्व प्रावधान था कि राष्ट्रपति 'अनुच्छेद 359' के अंतर्गत विशेष आदेश निकालकर संविधान के 'भाग 3' में दिए गए मूल अधिकारों में से जिन्हें उचित समझे न्यायालय से परिवर्तित कराए जाने का अधिकार निलंबित कर सकता है।
<p>12. 'उच्चतम न्यायालय' के अनुसार भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 21' की व्याख्या में समाविष्ट किया गया हैं -</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. विदेश यात्रा का अधिकार 2. एकांतता का अधिकार 3. नींद का अधिकार <p>कूट: (a) केवल 1 और 2 (b) केवल 1 और 3 (c) केवल 2 और 3</p>	<p>12. उत्तर -(d) 'अनुच्छेद 21' की विभिन्न व्याख्याएं की गईं और इसमें कई विषयों को समाविष्ट किया गया, जो हैं -</p> <ul style="list-style-type: none"> • त्वरित सुनवाई का अधिकार • एकांतता का अधिकार • पर्यावरण प्रदूषण के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार • अभियुक्तों तथा दोष सिद्ध अपराधियों के अधिकार • महिलाओं से संबंधित अधिकार • आश्रय का अधिकार • स्वास्थ्य का अधिकार तथा चिकित्सा सुविधा पाने का अधिकार • विदेश यात्रा का अधिकार • नींद का अधिकार या सोने का अधिकार

<p>(d) 1, 2 और 3</p>	<ul style="list-style-type: none"> इंटरनेट तक पहुँच का अधिकार <p>अतिरिक्त ज्ञान:</p> <p>अनुच्छेद 21- प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण</p> <ul style="list-style-type: none"> इसके तहत प्रावधान किया गया है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण व दैहिक स्वतंत्रता से 'विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया' के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। 'मेनका गांधी बनाम भारत संघ, 1978' के मामले में उच्चतम न्यायालय स्पष्ट किया कि न्यायालय व्यक्तियों को प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित करने वाली विधियों की संवैधानिकता पर विचार कर सकता है और यदि वह विधि युक्तियुक्त नहीं है तो उसे खारिज भी कर सकता है।
<p>13. भारतीय संविधान का 'अनुच्छेद 20' किसी व्यक्ति को निम्नलिखित में से कौन-सा/से अधिकार प्रदान करता है?</p> <ol style="list-style-type: none"> अपने विरुद्ध गवाही देने से संरक्षण गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के कारणों को जानने का अधिकार गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को वकील से सलाह लेने तथा अपने बचाव के लिए प्रबंध करने का अधिकार <p>कूट:</p> <p>(a) 1, 2 और 3</p> <p>(b) केवल 1 और 2</p> <p>(c) केवल 2 और 3</p> <p>(d) केवल 1 और 3</p>	<p>13. उत्तर -(c)</p> <p>अनुच्छेद 20 - अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण</p> <p>भारतीय संविधान का 'अनुच्छेद 20' प्रावधान करता है कि राज्य किसी व्यक्ति को मनमाने तरीके से दंडित ना कर सके। इस संबंध में तीन व्यवस्था है -</p> <p>अनुच्छेद 20 (1) - भूतलक्षी दंडिक विधियों से संरक्षण</p> <ul style="list-style-type: none"> इसका अर्थ है कि कोई कार्य अपराध है या नहीं, यह कार्य करने के समय लागू विधि के अनुसार ही निर्धारित होगा, बाद में बनाई गई विधि के अनुसार नहीं। इसके तहत प्रावधान किया गया है कि आपराधिक कृत्य करने के समय विधि उस कृत्य के लिए जो दंड प्रस्तावित करती है, किसी भी व्यक्ति को उससे अधिक दंड नहीं दिया जा सकेगा। <p>अनुच्छेद 20 (2) - दोहरे दंड से संरक्षण</p> <ul style="list-style-type: none"> यह अनुच्छेद प्रावधान करता है कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 1 बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। <p>अनुच्छेद 20 (3) - अपने विरुद्ध गवाही देने से संरक्षण</p> <ul style="list-style-type: none"> इसके अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। <p>अनुच्छेद 22 - कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण</p> <p>भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 22' में नागरिकों को प्राप्त निम्नलिखित अधिकारों का उल्लेख है -</p> <ul style="list-style-type: none"> गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के कारणों को जानने का अधिकार गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को वकील से सलाह लेने तथा अपने बचाव के लिए प्रबंध करने का अधिकार गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटों के भीतर निकट मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक होगा (गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक की यात्रा समय को छोड़कर) मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना किसी भी व्यक्ति को 24 घंटे से ज्यादा समय के लिए गिरफ्तार नहीं रखा जा सकता है। <p>अतिरिक्त ज्ञान:</p> <p>निवारक निरोध ⁹</p> <ul style="list-style-type: none"> 'निवारक निरोध' का अर्थ है किसी व्यक्ति को बिना मुकदमे और न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि के निरुद्ध करना। इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति को पिछले

	<p>अपराध के लिये दंडित करना नहीं है बल्कि उसे निकट भविष्य में अपराध करने से रोकना है।</p> <ul style="list-style-type: none"> • किसी व्यक्ति की हिरासत तीन महीने से अधिक नहीं हो सकती है जब तक कि एक सलाहकार बोर्ड विस्तारित हिरासत के लिये पर्याप्त कारण की रिपोर्ट नहीं करता है। • भारतीय संविधान का 'अनुच्छेद 22' गिरफ्तार या हिरासत में लिये गए व्यक्तियों को संरक्षण प्रदान करता है। • 'अनुच्छेद 22' के दो भाग हैं - पहला भाग सामान्य कानून के मामलों से संबंधित है और दूसरा भाग निवारक निरोध कानून के मामलों से संबंधित है।
<p>14. नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक कथन (A) और दूसरा कारण (R) है।</p> <p>कथन (A): भारत में बंधुआ मजदूरी समाप्त करने के लिए वर्ष 1976 में 'बंधुआ मजदूरी का उन्मूलन अधिनियम' पारित किया गया था।</p> <p>कारण (R): भारतीय संविधान के अनुसार राज्य सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए सार्वजनिक सेवा या श्रम योजना लागू कर सकता है।</p> <p>नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए:</p> <p>(a) A तथा R दोनों सही हैं किंतु (R) (A) का सही स्पष्टीकरण नहीं है।</p> <p>(b) A असत्य है, किंतु R सत्य है।</p> <p>(c) A तथा R दोनों सही हैं और (A) का सही स्पष्टीकरण (R) है।</p> <p>(d) A सत्य है, किंतु R असत्य है।</p>	<p>14. उत्तर -(a)</p> <p>अनुच्छेद 23 - मानव दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध</p> <ul style="list-style-type: none"> • यह अनुच्छेद मानव दुर्व्यापार अर्थात् पुरुष, महिला एवं बच्चों की खरीद बिक्री और उनके अनैतिक दुर्व्यापार को प्रतिबंधित करता है। लेकिन राज्य सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए सार्वजनिक सेवा या श्रम योजना लागू कर सकता है। • राज्य इस सेवा में धर्म, मूलवंश, जाति या वर्ग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। • भारत में बंधुआ मजदूरी समाप्त करने के लिए वर्ष 1976 में बंधुआ मजदूरी का उन्मूलन अधिनियम पारित किया गया। अतः A तथा R दोनों सही हैं किंतु (R) (A) का सही स्पष्टीकरण नहीं है। <div data-bbox="613 989 1549 1293"> <p>अतिरिक्त ज्ञान:</p> <ul style="list-style-type: none"> • अनुच्छेद 24 - कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध • यह अनुच्छेद किसी फैक्ट्री, खान अथवा अन्य परिसंकटमय गतिविधियों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध करता है, परंतु यह प्रतिषेध किसी नुकसान ना पहुंचाने वाले अथवा निर्दोष कार्य में नियोजन का प्रतिषेध नहीं करता है। </div>
<p>15. भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 25' सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. इसके अनुसार देश के प्रत्येक नागरिक को किसी भी धर्म को मानने व आचरण करने और प्रचार करने का अधिकार है। 2. लोक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के आधार पर सरकार 'धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध' लगा सकती है। <p>उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?</p> <p>(a) 1 और 2 दोनों</p> <p>(b) केवल 2</p>	<p>15. उत्तर -(a)</p> <p>धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार</p> <ul style="list-style-type: none"> • भारतीय संविधान का 'अनुच्छेद 25' अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म की अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। • इसके अनुसार देश के प्रत्येक नागरिक को किसी भी धर्म को मानने व आचरण करने और प्रचार करने का अधिकार है। लेकिन लोक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के आधार पर सरकार 'धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध' लगा सकती है। • बलात् धर्म परिवर्तन का अधिकार 'धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार' के अन्तर्गत सम्मिलित नहीं है। <div data-bbox="613 1766 1549 1976"> <p>अतिरिक्त ज्ञान:</p> <p>भारतीय संविधान का 'अनुच्छेद 28' (कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता)</p> <ul style="list-style-type: none"> • (1) - राज्य-निधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा </div>

<p>(c) न तो 1, न ही 2 (d) केवल 1</p>	<p>नहीं दी जाएगी।</p> <ul style="list-style-type: none"> • (2) - खंड (1) की कोई बात ऐसी शिक्षा संस्था को लागू नहीं होगी जिसका प्रशासन राज्य करता है किंतु जो किसी ऐसे विन्यास या न्यास के अधीन स्थापित हुई है जिसके अनुसार उस संस्था में धार्मिक शिक्षा देना आवश्यक है। • (3) - राज्य से मान्यता प्राप्त या राज्य-निधि से सहायता पाने वाली शिक्षा संस्था में उपस्थित होने वाले किसी व्यक्ति को ऐसी संस्था में दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा में भाग लेने के लिए या ऐसी संस्था में या उससे संलग्न स्थान में की जाने वाली धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के लिए तब तक बाध्य नहीं किया जाएगा जब तक कि उस व्यक्ति ने, या यदि वह अवयस्क है तो उसके संरक्षक ने, इसके लिए अपनी सहमति नहीं दे दी है।
<p>16. भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 30' के अन्तर्गत 'अल्पसंख्यक' में सम्मिलित है -</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. केवल भाषाई अल्पसंख्यक 2. केवल धार्मिक अल्पसंख्यक <p>कूट:</p> <p>(a) न तो 1, न ही 2 (b) केवल 2 (c) केवल 1 (d) 1 और 2 दोनों</p>	<p>16. उत्तर -(d)</p> <p>भारतीय संविधान का 'अनुच्छेद 30' (शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक-वर्गों का अधिकार)</p> <ul style="list-style-type: none"> • भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 में ऐसे प्रावधान शामिल हैं जो समानता के सिद्धांत को भी ध्यान में रखते हुए देश में अल्पसंख्यक समुदाय के विभिन्न अधिकारों की रक्षा करते हैं। • अनुच्छेद 30(1) कहता है कि सभी अल्पसंख्यकों को, चाहे वे धर्म या भाषा पर आधारित हों, अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और संचालित करने का अधिकार होगा। • अनुच्छेद 30(1ए) अल्पसंख्यक समूहों द्वारा स्थापित किसी भी शैक्षणिक संस्थान की संपत्ति के अधिग्रहण के लिए राशि के निर्धारण से संबंधित है। • अनुच्छेद 30(2) में कहा गया है कि सरकार को सहायता देते समय किसी भी शैक्षणिक संस्थान के साथ इस आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए कि यह किसी अल्पसंख्यक के प्रबंधन में है, चाहे वह धर्म या भाषा के आधार पर हो। <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>अतिरिक्त ज्ञान:</p> <p>अनुच्छेद 29</p> <ul style="list-style-type: none"> • अनुच्छेद 29 यह प्रावधान करता है कि भारत के किसी भी भाग में रहने वाले नागरिकों के किसी भी अनुभाग को अपनी बोली, भाषा, लिपि या संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है। • इसके अतिरिक्त किसी भी नागरिक को राज्य के अंतर्गत आने वाले संस्थान या उससे सहायता प्राप्त संस्थान में धर्म, जाति या भाषा के आधार पर प्रवेश से रोका नहीं जा सकता। • अनुच्छेद 29 धार्मिक अल्पसंख्यकों एवं भाषायी अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करता है। • हालाँकि उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि इस अनुच्छेद की व्यवस्था केवल अल्पसंख्यकों तक ही सीमित नहीं है, जैसा कि सामान्यतः माना जाता है, क्योंकि 'नागरिकों के अनुभाग' शब्द का अभिप्राय अल्पसंख्यक एवं बहुसंख्यक दोनों से है। </div>
<p>17. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के</p>	<p>17. उत्तर -(b)</p>

अनुसार उच्चतम न्यायालय द्वारा 'परमादेश रिट' जारी की जा सकती है -

1. अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध
2. सार्वजनिक संस्थाओं के विरुद्ध
3. निजी व्यक्तियों या इकाई के विरुद्ध
4. संविदात्मक दायित्व को लागू करने के विरुद्ध

कूट:

- (a) केवल 2 और 3
(b) केवल 1 और 2
(c) केवल 1, 2 और 4
(d) केवल 1 और 4

परमादेश (Mandamus) रिट

इसका शाब्दिक अर्थ है "हम आदेश देते हैं" यह रिट तब जारी की जाती है जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक अधिकारी, न्यायालय अथवा निगम अपने कार्यों या संवैधानिक दायित्वों को करने में असफल रहता है। इस प्रकार यह न केवल सार्वजनिक संस्थाओं अपितु अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध भी जारी किया जा सकता है। यह रिट जारी नहीं की जा सकती है -

- निजी व्यक्तियों या इकाई के विरुद्ध
- संविदात्मक दायित्व को लागू करने के विरुद्ध
- जब कर्तव्य विवेकानुसार हों
- भारत के राष्ट्रपति है राज्यों के राज्यपालों के विरुद्ध

अतिरिक्त ज्ञान:

संवैधानिक उपचारों का अधिकार

- भारतीय संविधान के 'भाग - 3' द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से किसी को प्रवर्तित कराने के लिए उच्चतम न्यायालय (अनुच्छेद 32) और उच्च न्यायालय (अनुच्छेद 226) निदेश या आदेश या रिट जारी कर सकते हैं, जिनके अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार-पृच्छा और उत्प्रेषण रिट शामिल हैं।
- इस अनुच्छेद को 'संविधान की आत्मा' कहा जाता है। चूंकि संवैधानिक उपचार (रिट जारी करना) स्वयं में एक मूल अधिकार है अतः इसे उच्चतम न्यायालय द्वारा अस्वीकृत नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकारों का रक्षक एवं गारंटी देने वाला बनाया गया है।

18. 'प्रतिषेध (Prohibition) रिट' के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह रिट उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा तब जारी की जाती है जब किसी व्यक्ति द्वारा अवैधानिक रूप से कोई सार्वजनिक पद ग्रहण किया जाता है।
2. यह रिट केवल न्यायिक या अर्द्ध-न्यायिक प्राधिकरणों के विरुद्ध जारी की जा सकती है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
(b) न तो 1, न ही 2
(c) केवल 2
(d) 1 और 2 दोनों

18. उत्तर -(c)

प्रतिषेध (Prohibition) रिट

- यह रिट केवल न्यायिक या अर्द्ध-न्यायिक प्राधिकरणों के विरुद्ध जारी की जा सकती है। यह सार्वजनिक निकायों, विधायी निकायों व निजी व्यक्तियों के लिए उपलब्ध नहीं है।
- यह रिट उच्चतम न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों (उच्च न्यायालयों) और उच्च न्यायालयों द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालयों को अपने न्याय क्षेत्र से उच्च न्यायिक कार्यों को रोकने के लिए जारी की जाती है।

अतिरिक्त ज्ञान:

बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus)

- इसे लैटिन भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ है "मशरीर प्रस्तुत किया जाए"।
- बंदी प्रत्यक्षीकरण में न्यायालय उस व्यक्ति के सन्दर्भ में रिट जारी करता है जिसे किसी दूसरे के द्वारा हिरासत में रखा गया है, उसे न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया जाए और जांच कराए जाने पर यदि व्यक्ति निर्दोष है तो उसे स्वतंत्र किया जा सकता है

उत्प्रेषण (Certiorari)

- इसका अर्थ है - "प्रमाणित होना या सूचना देना" यह रिट भी अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध जारी की जाती है। इस रिट को जारी करके अधीनस्थ न्यायालयों को यह निर्देश दिया जाता है कि वे अपने पास संचित मुकदमे के निर्णय लेने के लिए उस मुकदमे को वरिष्ठ न्यायालय अथवा उच्चतर न्यायालय

	<p>को भेजें।</p> <ul style="list-style-type: none"> उत्प्रेषण रिट का मतलब उच्चतर न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में चल रहे किसी मुकदमे के प्रलेख की समीक्षा मात्र है, इसका तात्पर्य यह नहीं है कि उच्चतर न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध ही हो। वर्ष 1991 के बाद उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि उत्प्रेषण व्यक्तियों के अधिकारों को प्रभावित करने वाले प्रशासनिक प्राधिकरणों के खिलाफ भी जारी किया जा सकता है। यह किसी भी विधायी निकाय या निजी व्यक्तियों/इकाइयों के विरुद्ध जारी नहीं कर सकते। <p>अधिकार पृच्छा (Quo-Warranto)</p> <ul style="list-style-type: none"> यह रिट उच्चतम न्यायालय (SC) या उच्च न्यायालय (HC) द्वारा तब जारी की जाती है जब किसी व्यक्ति द्वारा अवैधानिक रूप से कोई सार्वजनिक पद ग्रहण किया जाता है। न्यायालय इस रिट द्वारा संबंधित व्यक्ति को पद छोड़ने का आदेश दे सकता है।
<p>19. 'भारतीय संविधान' के सन्दर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए:</p> <ol style="list-style-type: none"> अनुच्छेद 19 - वाक्-स्वातंत्र्य आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण अनुच्छेद 20 - अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण अनुच्छेद 24 - मानव दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध अनुच्छेद 26 - धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता <p>उपर्युक्त में से कितने युग्म सुमेलित है?</p> <p>(a) एक युग्म (b) दो युग्म (c) तीन युग्म (d) चार युग्म</p>	<p>19. उत्तर -(c)</p> <p>मौलिक अधिकारों से सम्बंधित प्रमुख अनुच्छेद</p> <ul style="list-style-type: none"> अनुच्छेद 19 - वाक्-स्वातंत्र्य आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण अनुच्छेद 23 - मानव दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध अनुच्छेद 24 - कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध अनुच्छेद 20 - अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण अनुच्छेद 26 - धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता <p>अतिरिक्त ज्ञान:</p> <p>अनुच्छेद 33 - 'भाग 3' द्वारा प्रदत्त अधिकारों का बलों आदि को लागू होने में, उपांतरण करने की संसद की शक्ति</p> <ul style="list-style-type: none"> 'अनुच्छेद 33' संविधान के भाग तीन का अपवाद है। अनुच्छेद 13 (2), यह उपबंधित करता है कि राज्य कोई भी ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो भाग 3 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को छीनती है या न्यून करती है, किन्तु अनुच्छेद 33, संसद को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह कुछ विशिष्ट वर्गों के सम्बन्ध में विशिष्ट प्रयोजनों की पूर्ति हेतु मूल अधिकारों को निर्बन्धित या निराकृत करने वाली विधि बना सकती है। ध्यातव्य है कि 'अनुच्छेद 33' के अन्तर्गत केवल संसद को विधि बनाने की शक्ति दी गयी है राज्य विधान मंडलों को नहीं।
<p>20. निम्नलिखित में से कौन सा/से 'मूल अधिकार' केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है/हैं?</p> <ol style="list-style-type: none"> अनुच्छेद 15 अनुच्छेद 19 अनुच्छेद 22 अनुच्छेद 29 <p>कूट:</p>	<p>20. उत्तर -(b)</p> <p>केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार</p> <ul style="list-style-type: none"> अनुच्छेद 15 - धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध अनुच्छेद 16 - लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता अनुच्छेद 19 - वाक्-स्वातंत्र्य आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण अनुच्छेद 29 - अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 30 - शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक

<p>(a) केवल 2 और 3 (b) केवल 1, 2 और 4 (c) केवल 1, 2 और 3 (d) केवल 3 और 4</p>	<p>वर्गों का अधिकार</p> <p>अतिरिक्त ज्ञान: भारतीय नागरिकों एवं विदेशियों को प्राप्त मूल अधिकार (शत्रु देश के लोगों को छोड़कर)</p> <ul style="list-style-type: none"> • अनुच्छेद 14 - विधि के समक्ष समता • अनुच्छेद 20 - अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण • अनुच्छेद 21 - प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण • अनुच्छेद 21 (A) - प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार • अनुच्छेद 22 - कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण शोषण के विरुद्ध अधिकार • अनुच्छेद 23 - मानव दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध • अनुच्छेद 24 - कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध • अनुच्छेद 25 - अंतःकरण की और धर्म की अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता • अनुच्छेद 26 - धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता • अनुच्छेद 27- किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता • अनुच्छेद 28 - कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता
<p>21. भारतीय संविधान के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. मौलिक अधिकार के रूप में 'निजता का अधिकार' अनुच्छेद 19 में निहित है। 2. न्यायमूर्ति के. एस. पुत्तास्वामी और बनाम भारत संघ वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने 'निजता के अधिकार' मौलिक अधिकार माना था। <p>उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?</p> <p>(a) केवल 1 (b) न तो 1, न ही 2 (c) केवल 2 (d) 1 और 2 दोनों</p>	<p>21. उत्तर -(c)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 'मौलिक अधिकार' के रूप में 'निजता का अधिकार' जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार (अनुच्छेद 21) में निहित है। • न्यायमूर्ति के. एस. पुत्तास्वामी और बनाम भारत संघ (2017) ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक निर्णय को दिया जिसमें कहा गया है कि 'निजता का अधिकार' मौलिक अधिकार है। <p>अतिरिक्त ज्ञान:</p> <ul style="list-style-type: none"> • भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त 'मौलिक अधिकार' निरंकुश या असीमित अधिकार नहीं हैं। सरकार मौलिक अधिकारों के प्रयोग पर 'औचित्यपूर्ण' प्रतिबंध लगा सकती है। मौलिक अधिकारों के हनन को रोकने की शक्ति और इसका उत्तरदायित्व न्यायपालिका के पास है। विधायिका या कार्यपालिका के किसी कार्य या निर्णय से यदि मौलिक अधिकारों का हनन होता है या उन पर अनुचित प्रतिबंध लगाया जाता है तो न्यायपालिका उसे अवैध घोषित कर सकती है।
<p>22. 'राज्य के नीति निर्देशक तत्वों' के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. इनका उल्लेख भारतीय संविधान के 'भाग 4' में अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है। 	<p>22. उत्तर -(d)</p> <ul style="list-style-type: none"> • भारतीय संविधान के 'भाग 4' में अनुच्छेद 36 से 51 तक 'राज्य के नीति निर्देशक तत्वों' का उल्लेख किया गया है। इनको न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता यानी कि नीति निर्देशक तत्वों को वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। <p>अतिरिक्त ज्ञान:</p>

<p>2. इन्हें वैधानिक शक्ति प्राप्त है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?</p> <p>(a) केवल 2 (b) 1 और 2 दोनों (c) न तो 1, न ही 2 (d) केवल 1</p>	<p>भारतीय संविधान के भाग</p> <ul style="list-style-type: none"> भाग III - मूलभूत अधिकार - अनुच्छेद 12 - 35 भाग IV - राज्य के नीति निर्देशक तत्व - अनुच्छेद 36 - 51 भाग IVA - मूल कर्तव्य - अनुच्छेद 51A भाग V - संघ - अनुच्छेद 52-151
<p>23. भारतीय संविधान के 'भाग 4' के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:</p> <p>1. इस भाग में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, "राज्य" का वही अर्थ है जो 'भाग III' में है।</p> <p>2. इस भाग में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे।</p> <p>उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?</p> <p>(a) 1 और 2 दोनों (b) केवल 2 (c) न तो 1, न ही 2 (d) केवल 1</p>	<p>23. उत्तर -(a)</p> <p>अनुच्छेद 36 (परिभाषा)</p> <ul style="list-style-type: none"> इस भाग में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, "राज्य" का वही अर्थ है जो 'भाग III' (अनुच्छेद 12) में है। <p>अनुच्छेद 37 ('भाग 4' में अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना)</p> <ul style="list-style-type: none"> इस भाग में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे किंतु फिर भी इनमें अधिकृत तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। <div data-bbox="613 779 1547 1018"> <p>अतिरिक्त ज्ञान:</p> <ul style="list-style-type: none"> भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 12' में राज्य की परिभाषा दी हुई है कि 'राज्य' के अंतर्गत भारत की सरकार और संसद तथा राज्यों में से प्रत्येक राज्य की सरकार और विधान-मंडल तथा भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी हैं। </div> <p style="text-align: center;"><small>join telegram https://t.me/pcsstudies1</small></p>
<p>24. नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक कथन (A) और दूसरा कारण (R) है।</p> <p>कथन (A): भारतीय संविधान का 'अनुच्छेद 39क' समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का उपबन्ध करता है।</p> <p>कारण (R): भारतीय संविधान का 'अनुच्छेद 43 (ख)' सहकारी समितियों के ऐच्छिक गठन से सम्बंधित है।</p> <p>नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए:</p> <p>(a) A तथा R दोनों सही हैं किंतु (R) (A) का सही स्पष्टीकरण नहीं है। (b) A असत्य है, किंतु R सत्य है। (c) A तथा R दोनों सही हैं और (A) का सही स्पष्टीकरण (R) है। (d) A सत्य है, किंतु R असत्य है।</p>	<p>24. उत्तर -(a)</p> <p>भारतीय संविधान का 'अनुच्छेद 39क' (समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता)</p> <ul style="list-style-type: none"> राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि विधिक तंत्र इस प्रकार काम करे कि समान अवसर के आधार पर न्याय सुलभ हो और आर्थिक या किसी अन्य निर्योग्यता के कारण कोई नागरिक न्याय प्राप्त करने के अवसर से वंचित न रह जाए। (42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा जोड़ा गया) संविधान के 'अनुच्छेद 43 (ख)' में राज्य सहकारी समिति के ऐच्छिक गठन, स्वायत्त कार्यवाही, लोकतान्त्रिक नियंत्रण और व्यावसायिक प्रबन्धन में वृद्धि करने हेतु राज्य सरकार के लिए नीति निर्देशक तत्व निर्धारित किये गये हैं। <div data-bbox="613 1560 1547 1812"> <p>अतिरिक्त ज्ञान:</p> <ul style="list-style-type: none"> अनुच्छेद 38 - राज्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करके और आय, स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को कम करके सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित और संरक्षित करके लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। </div> <p style="text-align: center;">15</p>
<p>25. भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 41'</p>	<p>25. उत्तर -(c)</p>

<p>के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:</p> <ol style="list-style-type: none"> यह अनुच्छेद राज्य को ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए निर्देशित करता है। इस अनुच्छेद के अनुसार राज्य कुछ मामलों में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार सुनिश्चित करेगा। <p>उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?</p> <p>(a) केवल 1 (b) न तो 1, न ही 2 (c) केवल 2 (d) 1 और 2 दोनों</p>	<p>अनुच्छेद 40. ग्राम पंचायतों का संगठन</p> <ul style="list-style-type: none"> राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियाँ और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो। संविधान का 'अनुच्छेद 41' राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। इस अनुच्छेद के अनुसार राज्य कुछ मामलों में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार सुनिश्चित करेगा। <p>अतिरिक्त ज्ञान: पंचायती राज संस्थान</p> <ul style="list-style-type: none"> पंचायती राज संस्थान भारत में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की एक प्रणाली है। 'स्थानीय स्वशासन' का अर्थ है स्थानीय लोगों द्वारा निर्वाचित निकायों द्वारा स्थानीय मामलों का प्रबंधन। ज़मीनी स्तर पर लोकतंत्र की स्थापना करने के लिये 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के माध्यम से पंचायती राज संस्थान को संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई और उन्हें देश में ग्रामीण विकास का कार्य सौंपा गया।
<p>26. निम्नलिखित में से किसने कहा था कि "राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधानुसार अदा किया जाता है।"</p> <p>(a) बी.आर.अम्बेडकर (b) के.टी.शाह (c) ग्रेनविले ऑस्टिन (d) बी.एन. राव</p>	<p>26.उत्तर -(b)</p> <ul style="list-style-type: none"> "राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधानुसार अदा किया जाता है।" - के.टी.शाह <p>अतिरिक्त ज्ञान:</p> <ul style="list-style-type: none"> "नीति निर्देशक तत्वों का बहुत बड़ा मुल्य है। ये भारतीय राजव्यवस्था के लक्ष्य 'आर्थिक लोकतंत्र' को निर्धारित करते हैं जैसा की 'राजनीतिक लोकतंत्र' में प्रकट होता है।" - बी.आर.अम्बेडकर 'निदेशक तत्व, सामाजिक क्रांति के उद्देश्यों की प्राप्ति का माध्यम हैं।' - ग्रेनविले ऑस्टिन "नीति निर्देशक तत्वों का राज्य के प्राधिकारियों के लिए शैक्षिक महत्व है।" - बी.एन. राव
<p>27. निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए:</p> <p>अनुच्छेद - विषय</p> <ol style="list-style-type: none"> अनुच्छेद 41 - काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं का उपबंध अनुच्छेद 42 - प्रसूति सहायता का उपबंध <p>उपर्युक्त युग्मों में से कौन-सा/से युग्म सुमेलित है/हैं?</p> <p>(a) केवल 2 (b) 1 और 2 दोनों (c) न तो 1, न ही 2</p>	<p>27. उत्तर -(a)</p> <ul style="list-style-type: none"> अनुच्छेद 42 - काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध संविधान का 'अनुच्छेद 41' के अनुसार राज्य कुछ मामलों में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार सुनिश्चित करेगा। <p>अतिरिक्त ज्ञान:</p> <ul style="list-style-type: none"> अनुच्छेद 43 (कर्मचारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि) राज्य, उपयुक्त विधान या आर्थिक संगठन द्वारा या किसी अन्य रूप से कृषि के, उद्योग के या अन्य प्रकार के सभी कर्मचारों को काम, निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर और अवकाश का संपूर्ण उपभोग सुनिश्चित करने वाली काम की दशाएं तथा सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर प्राप्त कराने का प्रयास करेगा और ग्रामों में कुटीर उद्योगों को वैयक्तिक या सहकारी आधार पर बढ़ाने का प्रयास करेगा।

(d) केवल 1

28. भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 43क' के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह अनुच्छेद राज्य को उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों की भागीदारी को सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित करता है।
2. इस प्रावधान को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा जोड़ा गया था।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) न तो 1, न ही 2
(b) केवल 1
(c) केवल 2
(d) 1 और 2 दोनों

28. उत्तर -(d)

भारतीय संविधान का 'अनुच्छेद 43क' (उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना)

- राज्य किसी उद्योग में लगे हुए उपक्रमों, स्थापनों या अन्य संगठनों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त विधान द्वारा या किसी अन्य रीति से कदम उठाएगा। (42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा जोड़ा गया)

अतिरिक्त ज्ञान:

- अनुच्छेद 43 ख - राज्य सहकारी समितियों के गठन, प्रबंधन और सम्पादन में अभिवृद्धि करने का प्रयास करेगा। ('97वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2011' द्वारा जोड़ा गया।)
- अनुच्छेद 43 - राज्य सभी कामगारों के लिये निर्वाह योग्य मज़दूरी और एक उचित जीवन स्तर सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा।

29. सूची I (भारतीय संविधान के प्रमुख अनुच्छेद) को सूची II (प्रावधान) से सुमेलित कीजिये:

सूची I	सूची II
A. अनुच्छेद 44	1. बच्चों को निशुल्क शिक्षा
B. अनुच्छेद 45	2. दुर्बल वर्गों के हितों की अभिवृद्धि
C. अनुच्छेद 46	3. समान सिविल संहिता
D. अनुच्छेद 47	4. लोक स्वास्थ्य का सुधार

नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए:

- (a) A-3, B-1, C-2, D-4
(b) A-3, B-2, C-1, D-4
(c) A-4, B-1, C-2, D-3
(d) A-4, B-2, C-1, D-3

29. उत्तर -(a)

भारतीय संविधान के प्रमुख अनुच्छेद

- अनुच्छेद 44 - नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता।
- अनुच्छेद 45 - राज्य 6 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के पूर्व-बाल्यकाल की देखरेख और उन्हें शिक्षा देने का प्रयास भी करेगा। (86वें संविधान संशोधन - 2002 द्वारा इसके मूल पाठ में परिवर्तन किया गया)
- अनुच्छेद 46 - अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि।
- अनुच्छेद 47 - पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊँचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य।

अतिरिक्त ज्ञान:

नीति निर्देशक सिद्धांत

- यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है।
- इसका वर्णन संविधान के भाग-4 में है।
- इसे लागू कराने के लिए न्यायालय नहीं जाया जा सकता है।
- इसके पीछे राजनीतिक मान्यता है।
- यह सरकार के अधिकारों को बढ़ाता है।
- यह राज्य सरकार के द्वारा लागू करने के बाद ही नागरिकों को प्राप्त होता है।

30. भारत के संविधान के अनुच्छेद 48क में राज्यों को क्या सुनिश्चित करने के लिए

30. उत्तर -(b)

- अनुच्छेद 48क - पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की

<p>निदेश दिया गया है?</p> <p>(a) दुधारू और वाहक पशुओं की नस्लों के परिरक्षण और सुधार</p> <p>(b) पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन</p> <p>(c) पूर्व-बाल्यकाल की देखरेख और शिक्षा</p> <p>(d) कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण</p>	<p>रक्षा (42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा जोड़ा गया)</p> <p>अतिरिक्त ज्ञान:</p> <p>अनुच्छेद 48 (कृषि और पशुपालन का संगठन)</p> <ul style="list-style-type: none"> राज्य, कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करने का प्रयास करेगा और विशिष्टता गायों और बछड़ों तथा अन्य दुधारू और वाहक पशुओं की नस्लों के परिरक्षण और सुधार के लिए और उनके वध का प्रतिषेध करने के लिए कदम उठाएगा।
<p>31. निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए:</p> <p>अनुच्छेद - प्रावधान</p> <ol style="list-style-type: none"> अनुच्छेद 49 - राष्ट्रीय महत्व के संस्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। अनुच्छेद 50 - अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। अनुच्छेद 51 - कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। <p>उपर्युक्त में से कितने युग्म सुमेलित हैं?</p> <p>(a) एक</p> <p>(b) दो</p> <p>(c) तीन</p> <p>(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं</p>	<p>31. उत्तर -(a)</p> <ul style="list-style-type: none"> अनुच्छेद 49 - राष्ट्रीय महत्व के संस्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। अनुच्छेद 50 - कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 51 - अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। <p>अतिरिक्त ज्ञान:</p> <ul style="list-style-type: none"> भारतीय संविधान का 'अनुच्छेद 253' संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए कानून बनाने का अधिकार देता है। यह भारत सरकार को सभी अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों और प्रतिबद्धताओं को लागू करने में सक्षम बनाता है।
<p>32. 'सरदार स्वर्ण सिंह समिति' के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:</p> <ol style="list-style-type: none"> इस समिति की अनुशंसाओं के आधार पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। 'सी. एम. स्टीफन' इस समिति के एक सदस्य थे। <p>उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?</p> <p>(a) केवल 1</p> <p>(b) न तो 1, न ही 2</p> <p>(c) 1 और 2 दोनों</p> <p>(d) केवल 2</p>	<p>32. उत्तर -(c)</p> <ul style="list-style-type: none"> भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को 'सरदार स्वर्ण सिंह समिति' की अनुशंसाओं के आधार पर जोड़ा गया था। स्वर्ण सिंह समिति (1976) के सदस्य थे - <ul style="list-style-type: none"> ए. आर. अंतुले एस. एस. रे सी. एम. स्टीफन <p>अतिरिक्त ज्ञान:</p> <ul style="list-style-type: none"> यद्यपि स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को जोड़ने का सुझाव दिया था, परंतु 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से 10 मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। इसके पश्चात् 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से एक और मूल कर्तव्य जोड़ा गया, वर्तमान में इनकी संख्या 11 है।
<p>33. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:</p> <ol style="list-style-type: none"> भारतीय संविधान में 'मूल कर्तव्यों' को आयरलैंड के 	<p>33. उत्तर -(a) 18</p> <ul style="list-style-type: none"> भारतीय संविधान में 'मूल कर्तव्यों' को पूर्व सोवियत संघ (वर्तमान रूस) के संविधान से लिया गया है। 'मूल कर्तव्य' केवल भारतीय नागरिकों के लिए हैं ना कि विदेशियों के लिए।

<p>संविधान से लिया गया है।</p> <p>2. 'मूल कर्तव्य' केवल भारतीय नागरिकों के लिए हैं ना कि विदेशियों के लिए।</p> <p>उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?</p> <p>(a) केवल 2</p> <p>(b) न तो 1, न ही 2</p> <p>(c) केवल 1</p> <p>(d) 1 और 2 दोनों</p>	<p>अतिरिक्त ज्ञान:</p> <ul style="list-style-type: none"> भारतीय संविधान में वर्णित मूल कर्तव्य 'अप्रवर्तनीय' हैं। संविधान में सीधे न्यायालय के माध्यम से उनके क्रियान्वयन की व्यवस्था नहीं दी गई है।
<p>34. निम्नलिखित में से कौन-सा/से भारतीय संविधान में वर्णित 'मूल कर्तव्य' है/हैं?</p> <ol style="list-style-type: none"> भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना। मानवतावाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा ज्ञानार्जन एवं सुधार की भावना का विकास करना। संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्र गान का आदर करना। 6 से 14 वर्ष तक के आयु के अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना। <p>कूट:</p> <p>(a) केवल 1, 2 और 3</p> <p>(b) केवल 2, 3 और 4</p> <p>(c) 1, 2, 3 और 4</p> <p>(d) केवल 1, 3 और 4</p>	<p>उत्तर -(c)</p> <p>भारतीय संविधान में वर्णित 'मूल कर्तव्य' [भाग 4(क), अनुच्छेद 51(क)] भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह -</p> <ol style="list-style-type: none"> संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्र गान का आदर करना। स्वतंत्रता के लिये हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों का पालन करना। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना। देश की रक्षा करना और आह्वान किये जाने पर राष्ट्र की सेवा करना। भारत के लोगों में समरसता और समान भावतुत्व की भावना का निर्माण करना जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी प्रकार के भेदभाव से परे हो। साथ ही ऐसी प्रथाओं का त्याग करना जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं। हमारी समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना और संरक्षित करना। वनों, झीलों, नदियों और वन्यजीवन सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा एवं सुधार करना और प्राणिमात्र के लिए दयाभाव रखना। मानवतावाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा ज्ञानार्जन एवं सुधार की भावना का विकास करना। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना एवं हिंसा से दूर रहना। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिये प्रयास करना ताकि राष्ट्र लगातार उच्च स्तर की उपलब्धि हासिल करे। 6 से 14 वर्ष तक के आयु के अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना। <p>(86वें संविधान द्वारा जोड़ा गया)</p> <p>अतिरिक्त ज्ञान:</p> <p>वर्तमान में अनुच्छेद 51(A) के तहत वर्णित 11 मौलिक कर्तव्य हैं, जिनमें से 10 को 42वें संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था जबकि 11वें मौलिक कर्तव्यों को वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन के जरिये संविधान में शामिल किया गया था।</p> <ul style="list-style-type: none"> (11) यदि माता-पिता या संरक्षक है, छह वर्ष से चौदह वर्ष तक की आयु वाले अपने, यथास्थिति, बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करे। यह कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से जोड़ा गया।

<p>35. निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सत्य है/हैं?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. भारतीय संविधान में 'मौलिक कर्तव्यों' के तहत नैतिक और नागरिक दोनों ही प्रकार के कर्तव्य शामिल किये गए हैं। 2. 'स्वतंत्रता के लिये हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों का पालन करना' एक नैतिक कर्तव्य है। <p>नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए:</p> <p>(a) न तो 1, न ही 2 (b) 1 और 2 दोनों (c) केवल 1 (d) केवल 2</p>	<p>35. उत्तर -(b)</p> <ul style="list-style-type: none"> • भारतीय संविधान में 'मौलिक कर्तव्यों' के तहत नैतिक और नागरिक दोनों ही प्रकार के कर्तव्य शामिल किये गए हैं। • उदाहरण के लिये 'स्वतंत्रता के लिये हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों का पालन करना' एक नैतिक कर्तव्य है, जबकि 'संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रीय गान का आदर करना' एक नागरिक कर्तव्य है। <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>अतिरिक्त ज्ञान:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 'संयुक्त राज्य अमेरिका' द्वारा अपने नागरिकों को 'सिटिज़न्स अल्मनाक' नाम से एक दस्तावेज़ जारी किया जाता है जिसमें सभी नागरिकों के कर्तव्यों का विवरण दिया होता है। </div>
<p>36. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 'राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों' की अवधारणा का स्रोत 'स्पेनिश संविधान' है जहाँ से यह 'आयरिश संविधान' में आया था। 2. वर्ष 1999 में नियुक्त नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों पर 'वर्मा समिति' कुछ मौलिक कर्तव्यों के कार्यान्वयन हेतु कानूनी प्रावधानों के अस्तित्व की पहचान करती है। <p>उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?</p> <p>(a) केवल 2 (b) केवल 1 (c) न तो 1, न ही 2 (d) 1 और 2 दोनों</p>	<p>36. उत्तर -(d)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 'राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों' की अवधारणा का स्रोत 'स्पेनिश संविधान' है जहाँ से यह 'आयरिश संविधान' में आया था। • वर्ष 1999 में नियुक्त नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों पर 'वर्मा समिति' कुछ मौलिक कर्तव्यों के कार्यान्वयन हेतु कानूनी प्रावधानों के अस्तित्व की पहचान करती है। • 'वर्मा समिति' का उद्देश्य प्रत्येक शिक्षण संस्थान में मौलिक कर्तव्यों को लागू करने और सभी विद्यालयों में इन कर्तव्यों को सिखाने के लिये दुनिया भर में शुरू किये गए कार्यक्रम हेतु एक रणनीति और कार्यप्रणाली तैयार करना था। समिति ने अपनी जाँच में पाया कि देश के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों के गैर-परिचालन का मुख्य कारण इसके कार्यान्वयन हेतु रणनीति की कमी है। <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>अतिरिक्त ज्ञान:</p> <ul style="list-style-type: none"> • भारतीय संविधान में वर्णित 'राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों' का उद्देश्य लोगों के लिये सामाजिक-आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना और भारत को एक 'कल्याणकारी राज्य' के रूप में स्थापित करना है। </div>
<p>37. निम्नलिखित में से कौन-सा/से अनुच्छेद '42वें संविधान संशोधन, 1976' भारतीय संविधान में सम्मिलित किया/किये गया/गए था/थे?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. अनुच्छेद 39A 2. अनुच्छेद 43A 3. अनुच्छेद 48A 	<p>37. उत्तर -(b)</p> <p>भारतीय संविधान के 'भाग-IV' में संशोधन-42वाँ संविधान संशोधन, 1976</p> <ul style="list-style-type: none"> • अनुच्छेद 39A - गरीबों को निशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करना। • अनुच्छेद 43A - उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। • अनुच्छेद 48A - पर्यावरण की रक्षा और उसमें सुधार करना।

<p>कूट:</p> <p>(a) केवल 2</p> <p>(b) 1, 2 और 3</p> <p>(c) केवल 1 और 2</p> <p>(d) केवल 3</p>	<p>अतिरिक्त ज्ञान:</p> <p>44वाँ संविधान संशोधन, 1977 - इसने धारा 2 को अनुच्छेद 38 में सम्मिलित किया जो घोषित करता है कि "राज्य विशेष रूप से आय में आर्थिक असमानताओं को कम करने और व्यक्तियों के बीच नहीं बल्कि समूहों के बीच स्थिति, सुविधाओं एवं अवसरों संबंधी असमानताओं को खत्म करने का प्रयास करेगा।"</p> <ul style="list-style-type: none"> इसने मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को भी समाप्त कर दिया। <p>86वाँ संशोधन अधिनियम (2002) - इसने अनुच्छेद 45 की विषय-वस्तु को बदल दिया और प्रारंभिक शिक्षा को अनुच्छेद 21A के तहत मौलिक अधिकार बना दिया।</p> <p>91वाँ संशोधन अधिनियम (2011) - अनुच्छेद 43ख में 'सहकारी समिति' शब्द को जोड़ा गया था।</p>
<p>38. नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक कथन (A) और दूसरा कारण (R) है।</p> <p>कथन (A): 'मौलिक अधिकार' प्रकृति में नकारात्मक या निषेधात्मक हैं।</p> <p>कारण (R): वे राज्य पर सीमाएँ आरोपित करते हैं।</p> <p>नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए:</p> <p>(a) A तथा R दोनों सही हैं किंतु (R) (A) का सही स्पष्टीकरण नहीं है।</p> <p>(b) A असत्य है, किंतु R सत्य है।</p> <p>(c) A सत्य है, किंतु R असत्य है।</p> <p>(d) A तथा R दोनों सही हैं और (A) का सही स्पष्टीकरण (R) है।</p>	<p>38. उत्तर -(d)</p> <p>'मौलिक अधिकार' बनाम 'राज्य के नीति निदेशक तत्व'</p> <ul style="list-style-type: none"> मौलिक अधिकारों (FRs) के विपरीत राज्य के नीति निदेशक तत्वों (DPSPs) का दायरा असीम है और यह एक नागरिक के अधिकारों की रक्षा करता है और वृहद स्तर पर कार्य करता है। DPSP में वे सभी आदर्श शामिल हैं जिनका पालन राज्य को देश के लिये नीतियाँ और कानून बनाते समय ध्यान में रखना चाहिये। 'मौलिक अधिकार' प्रकृति में नकारात्मक या निषेधात्मक हैं क्योंकि वे राज्य पर सीमाएँ आरोपित करते हैं। अतः A तथा R दोनों सही हैं और (A) का सही स्पष्टीकरण (R) है। दूसरी ओर 'निदेशक सिद्धांत' सकारात्मक निर्देश हैं, जो कानून द्वारा प्रवर्तनीय नहीं हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि DPSP और मौलिक अधिकार साथ-साथ चलते हैं। DPSP मौलिक अधिकार के अधीनस्थ नहीं है। <p>अतिरिक्त ज्ञान:</p> <ul style="list-style-type: none"> भारतीय संविधान में वर्णित 'राज्य के निदेशक सिद्धांत' सकारात्मक निर्देश हैं, जो कानून द्वारा प्रवर्तनीय नहीं हैं।
<p>39. भारतीय संविधान में वर्णित निम्नलिखित में से कौन सा/से निदेशक तत्व 'गांधीवादी सिद्धांतों' पर आधारित है/हैं?</p> <ol style="list-style-type: none"> ग्राम पंचायतों का गठन। कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने का प्रयास। पुरुषों और महिलाओं दोनों को समान कार्य के लिये समान वेतन। सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन। 	<p>39. उत्तर -(c)</p> <p>गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित निर्देश</p> <ul style="list-style-type: none"> अनुच्छेद 40 - ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 43 - कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने का प्रयास। अनुच्छेद 43B - सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन। अनुच्छेद 46 - समाज के कमज़ोर वर्गों, विशेषकर एससी, एसटी शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा। अनुच्छेद 47 - सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार, नशा सेवन पर रोक। अनुच्छेद 48 - गायों, बछड़ों और अन्य दुधारू पशुओं के वध पर रोक लगाने तथा

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।

- (a) 1, 2, 3 और 4
(b) केवल 2 और 4
(c) केवल 1, 2 और 4
(d) केवल 1 और 3

मवेशियों को पालने एवं उनकी नस्लों में सुधार करने के लिये।

अतिरिक्त ज्ञान:

समाजवादी सिद्धांतों पर आधारित निर्देश

अनुच्छेद 38 - राज्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित कर आय, स्थिति, सुविधाओं तथा अवसरों में असमानताओं को कम करके सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित एवं संरक्षित कर लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा।

अनुच्छेद 39 - राज्य विशेष रूप से निम्नलिखित नीतियों को सुरक्षित करने की दिशा में कार्य करेगा:

- सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन का अधिकार।
- भौतिक संसाधनों के स्वामित्व और नियंत्रण को सामान्य जन की भलाई के लिये व्यवस्थित करना।
- कुछ ही व्यक्तियों के पास धन को संकेंद्रित होने से बचना।
- पुरुषों और महिलाओं दोनों को समान कार्य के लिये समान वेतन।
- श्रमिकों की शक्ति और स्वास्थ्य की सुरक्षा।
- बच्चों के बचपन एवं युवाओं का शोषण न होने देना।

अनुच्छेद 41 - बेरोज़गारी, बुढ़ापा, बीमारी और विकलांगता के मामलों में कार्य करने, शिक्षा पाने और सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार सुरक्षित करना।

अनुच्छेद 42 - राज्य काम की न्यायसंगत और मानवीय परिस्थितियों को सुनिश्चित करने एवं मातृत्व राहत के लिये प्रावधान करेगा।

अनुच्छेद 43 - राज्य सभी कामगारों के लिये निर्वाह योग्य मज़दूरी और एक उचित जीवन स्तर सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा।

अनुच्छेद 43A - उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिये राज्य कदम उठाएगा। Join telegram <https://t.me/pcsstudies1>

अनुच्छेद 47 - लोगों के पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाना और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करना।

उदार-बौद्धिक सिद्धांतों पर आधारित निर्देश

- **अनुच्छेद 44** - समान नागरिक संहिता।
- **अनुच्छेद 45** - सभी बच्चों को छह वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा प्रदान करना।
- **अनुच्छेद 48** - कृषि और पशुपालन को आधुनिक एवं वैज्ञानिक आधार पर संगठित करना।
- **अनुच्छेद 48A** - पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना तथा देश के वनों एवं वन्यजीवों की रक्षा करना।
- **अनुच्छेद 49** - राज्य की कलात्मक या ऐतिहासिक महत्त्व के प्रत्येक स्मारक या स्थान की रक्षा करना।
- **अनुच्छेद 50** - राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिये कदम उठाना।

40. भारतीय सर्वोच्च न्यायालय '86वाँ संशोधन अधिनियम 2002' प्रभावित करता है -

1. मौलिक अधिकारों को
2. राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को
3. मौलिक कर्तव्यों को

40. उत्तर -(d)

86वाँ संशोधन अधिनियम 2002

इसके द्वारा -

- अनुच्छेद 21(A) के तहत प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया। (मौलिक अधिकार)

कूट:

- (a) केवल 1 और 3
- (b) केवल 1
- (c) केवल 1 और 2
- (d) 1, 2 और 3

- नीति-निदेशक तत्वों के अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु को बदल दिया गया। (राज्य के नीति निदेशक तत्व)
- अनुच्छेद 51(A) में एक नया मौलिक कर्तव्य (11वाँ) जोड़ा गया। (मौलिक कर्तव्य)

अतिरिक्त ज्ञान:

- भारतीय संविधान का 'अनुच्छेद 44' समान नागरिक संहिता को परिभाषित करता है। अनुच्छेद 44 कहता है, 'राज्य पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा।' यह अनुच्छेद राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों का एक हिस्सा है।

join telegram <https://t.me/psstudies1>